

कोविड -19: महामारी का भारत के सुभेद्य (VULNERABLE) वर्गों पर प्रभाव

कैसे मौजूदा असमानताओं और भेद्यताओं (VULNERABILITIES) का भारत की प्रतिक्रिया और तैयारी पर दुष्प्रभाव पड़ा?

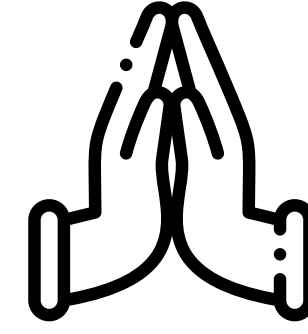
कोविड-19 ने भारत के गरीब एवं सुभेद्य वर्गों पे अनिश्चिता बढ़ाई जिसके कारण उन्हें असुरक्षा, लांछन (stigma) और आजीविका का नुक्सान झेलना पड़ा ।

SSHAP | Social Science in Humanitarian Action Platform

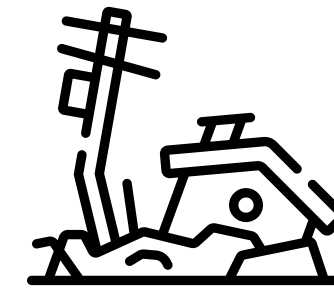
www.socialscienceinaction.org

@SSHAP_Action #SSHAP

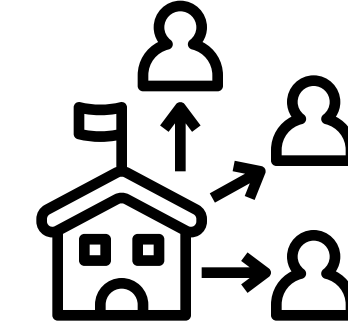
DOI: [10.19088/SSHAP.2021.008](https://doi.org/10.19088/SSHAP.2021.008)



भारत में महामारी के प्रभाव धर्म, वर्ग, जाति, एवं लिंग के आधार पर विभेदित रहे । सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव सुभेद्य वर्गों एवं अल्पसंख्यक समुदायों जैसे की मुसलमानों, दलितों और प्रवासी मजदूरों को झेलने पड़े ।



भारत के कई हिस्सों को लॉकडाउन के प्रतिबन्ध और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के साथ साथ लू, बाढ़ों और चक्रवात का भी सामना करना पड़ा है । कोविड-19 और इन आपदाओं की मार एक साथ पड़ने से राहत, बचाव और मानवीय सहायता के कार्यों में बाधाएँ आयी और आपदाओं से उबरने में परेशानी हुई ।

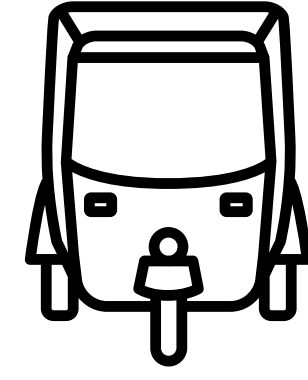


भारत के विस्तृत भौगोलिक आकार और विविधता के चलते किसी भी आपदा के प्रति समरूप प्रतिक्रिया प्रणाली बहुत कारगर नहीं रहतीं । एक सख्त सरकारी लॉकडाउन ने ग्रामीण और अनौपचारिक शहरी आजीविकाओं को नष्ट कर दिया, जिसके कारण कई शहरों से प्रवासी मज़दूरों का अव्यवस्थात्मक पलायन देखने को मिला ।

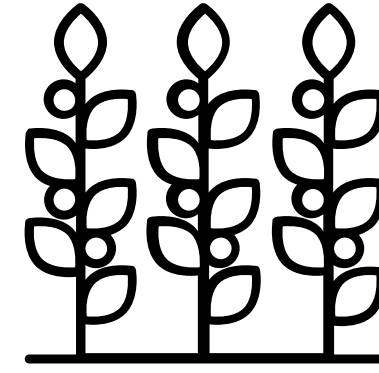
कोविड -19: महामारी का भारत के सुभेद्य (VULNERABLE) वर्गों पर प्रभाव

कोविड-19 ने मौजूदा अनिश्चितताओं को बढ़ाया

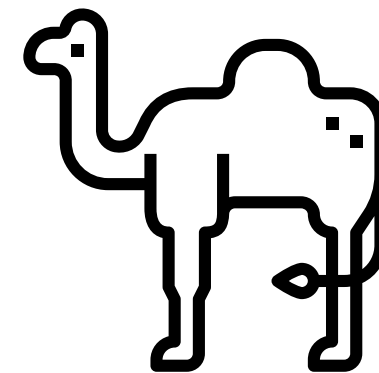
भारत में कोविड-19 महामारी एक तनाव गुड़क के रूप में सिद्ध हुई जिसने कृषि और आहार, जल और स्वच्छता, रोज़गार, स्वास्थ्य, जलवायु एवं आपदा प्रतिक्रिया के क्षेत्रों में काफी अनिश्चितताओं को बढ़ाया ।



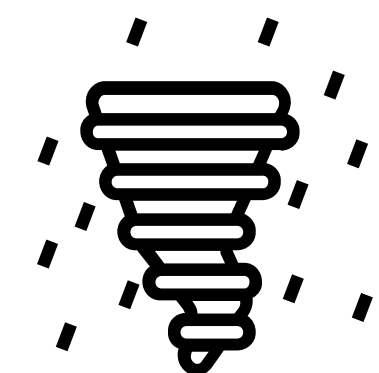
कोविड-19 ने यह दर्शाया की भारत के शहर किस हद तक अपनी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर करते हैं । व्यापार और वाणिज्य पर रोक लगने से एक बहुत बड़ी संख्या में अनौपचारिक श्रमिकों को आय का नुकसान झेलना पड़ा । जमा पूँजी के अभाव में उन्हें अपनी आजीविका से भी हाथ धोना पड़ा ।



ग्रामीण इलाकों में लॉकडाउन ने सर्दियों की फसल की कटाई को बाधित किया जिससे फसल की वितरण और बिक्री में काफी समस्याएं आयी । इन समस्याओं से उबरने के लिए कई किसानों ने निर्वाह फसलें उगाई और कड़्यों ने खाद्य व्यवस्था में ही रहकर अलग-अलग मॉडलों जैसे डायरेक्ट फार्म टू होम डिलवरी का सहारा लिया ।



गुजरात में कच्छ के सूखे इलाकों में जाट और रबारी पशु चारक लॉकडाउन के दौरान मंडियों और बाज़ारों तक नहीं पहुंच सके । ऐसी परिस्थितियों से वह निर्वाह आजीविका (subsistence livelihoods) के साधनों को अपनाया और अपने जीवन यापन के लिए स्थानीय किसानों की सहायता भी ली ।



लॉकडाउन के प्रतिबंधों ने आपदा से जुड़ी प्रतिक्रिया, राहत और बचाव कार्यों को भी बाधित किया । पश्चिम बंगाल में सुपर साइक्लोन अम्फान के साथ साथ लॉकडाउन और प्रवासी मजदूरों की वापसी के कारण प्रदेश के प्राधिकरण वर्ग के लिए साइक्लोन से प्रभावित शरणार्थियों के लिए आश्रय घर जुटाना एक कड़ी चुनौती साबित हुई ।

SSHAP | Social Science in
Humanitarian Action Platform

www.socialscienceinaction.org

@SSHAP_Action #SSHAP

DOI: [10.19088/SSHAP.2021.008](https://doi.org/10.19088/SSHAP.2021.008)

कोविड -19: महामारी का भारत के सुभेद्य (VULNERABLE) वर्गों पर प्रभाव

कोविड-19 महामारी का सुभेद्य वर्गों पे क्या प्रभाव पड़ा?

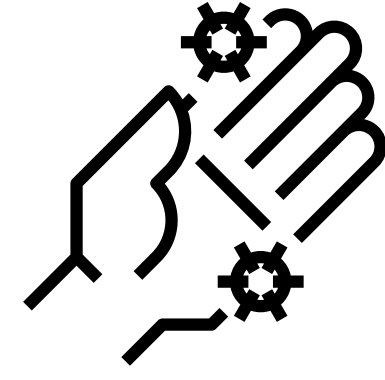
इस महामारी ने भारतीय समाज के उन मौजूदा संरचनात्मक असमानताओं को दर्शाया है जिनसे समाज के कई वर्गों को हाशिये पे रखा गया । विभिन्न समुदायों और वर्गों पे इस महामारी के विभेदित दुष्प्रभाव पड़े है ।

SSHAP | Social Science in
Humanitarian Action Platform

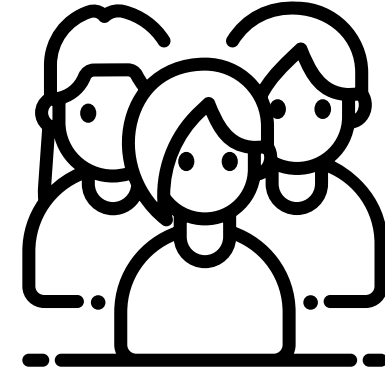
www.socialscienceinaction.org

@SSHAP_Action #SSHAP

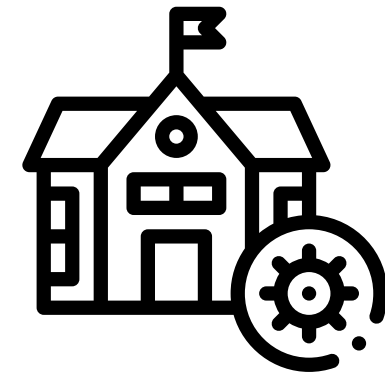
DOI: [10.19088/SSHAP.2021.008](https://doi.org/10.19088/SSHAP.2021.008)



भारत में कई वर्गों को जैसे दलितों, मुसलमानो, लौटते हुए प्रवासी मजदूर और उत्तर पूर्व के लोगों को वायरस फैलाने वाले वर्गों की उपाधि देकर लांछित किया गया ।



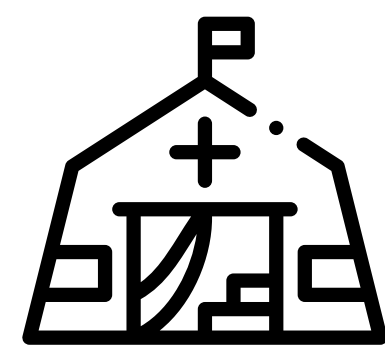
पुरुषों की तुलना में महिलाओं को इस महामारी के ज़्यादा दुष्प्रभाव झेलने पड़े है । अधिकाँश ऐसा देखा गया की उन्हें काम का नुक्सान हुआ और उन्होंने परिवार संयोजन एवं स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव को भी महसूस किया ।



प्रेषित धन और ग्रामीण आजीविकाओं पर रोक लगने से कई छात्रों की पढ़ाई में भी बाधा आयी और कइयों को स्कूल भी छोड़ना पड़ा । इसी प्रकार से स्कूल अनिश्चितकालीन रूप से बंद होने के कारण सरकार के कई भोजन राशन और टीकाकरण कार्यक्रमों पर भी रोक लग गयी जो पहले सरकारी स्कूलों के माध्यम से चलाए जाते थे ।



सरकार ने नकद हस्तांतरण और अन्य डायरेक्ट बेनिफिट स्कीमों के माध्यम से राहत कार्यों को किया, किन्तु इन स्कीमों का लाभ कई लोगों तक नहीं पहुंच सका । क्योंकि कई स्कीमों के लाभ तब ही मिल सकते थे यदि किसी के पास बैंक खाता, बायोमेट्रिक आई डी, राशन कार्ड या एक स्थायी पता हो ।



मार्च और अप्रैल के महीनो में अनुमानित 2.2-2.5 करोड़ अंतर्देशीय प्रवासियों का पलायन भारत के कई शहरों से अपने गाँवों और घरों की ओर देखने को मिला । क्योंकि परिवहन सेवाएं बंद थी, कई प्रवासियों को पैदल ही चल के अपने अपने गाँवों और कस्बों की ओर जाना पड़ा । ऐसी विषम परिस्थितियों में इनकी सहायता केवल कुछ गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित राहत शिविरों ने ही की ।

कोविड -19: महामारी का भारत के सुभेद्य (VULNERABLE) वर्गों पर प्रभाव

महामारी के बाद परिवर्तन और बहाली (रिकवरी)

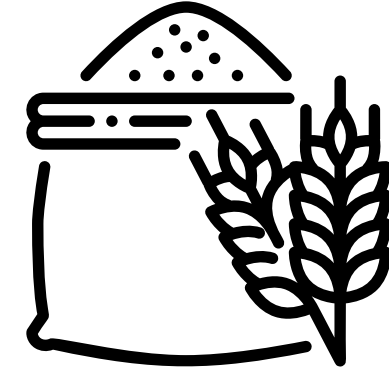
हालाँकि कोविड-19 से उबरने की प्रक्रिया धीमी, चयनात्मक और असमान रही है फिर भी महामारी के बाद के समय ने स्थायी और समावेशी आजीविकाओं के निर्माण के साथ-साथ सुभेद्य वर्गों की सुरक्षा के भी कई अवसर प्रस्तुत किये हैं।

SSHAP | Social Science in
Humanitarian Action Platform

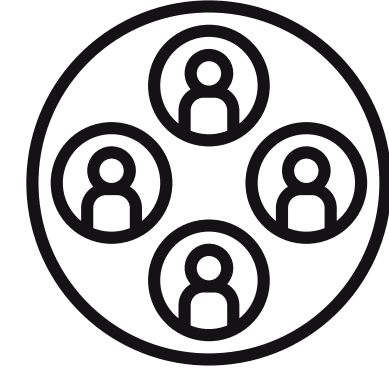
www.socialscienceinaction.org

@SSHAP_Action #SSHAP

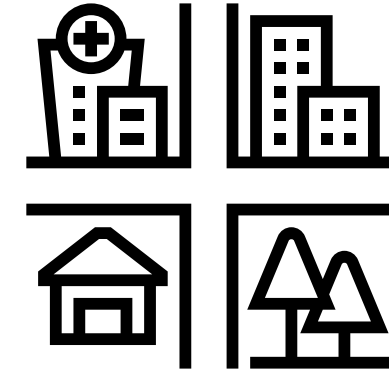
DOI: [10.19088/SSHAP.2021.008](https://doi.org/10.19088/SSHAP.2021.008)



अल्पकालिक उपायों से तत्काल राहत और बचाव के कार्यों को बल मिला है। अब दीर्घकालीन प्रतिक्रियाओं की ज़रूरत है जिनके माध्यम से लोगों की मौलिक आवश्यकताएं जैसे की खाना, पानी, आश्रय और आजीविका जैसी आवश्यकताओं की पूर्ती सुनिश्चित की जा सके।



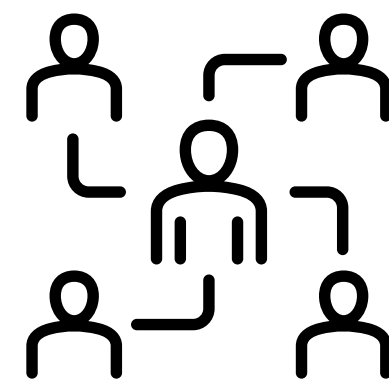
सरकार की नीतियों को सुभेद्य वर्गों की आवाज़ें और अनुभव एक नयी दिशा दें और इस प्रणाली में सिविल सोसाइटी संगठनों की भी एक एहम भूमिका हो।



प्रवासी मज़दूरों के निष्क्रमण ने ग्रामीण पुनरुत्थान (rural revival) के कई अवसर प्रदान किये हैं। मौजूदा ग्रामीण रोज़गार स्कीमों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की आधारिक संरचना को बेहतर किया जा सकता है। इससे सामुदायिक सम्पदा में भी बढ़ोतरी होगी और कृषि के अलावा भी कई श्रम घनिष्ठ आजीविकाओं को बल मिलेगा।



महामारी के दौरान सरकार की राहत और सामाजिक सुरक्षा की नीतियों और स्कीमों की सीमित पहुंच ने एक सार्वभौमिक (universal) सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की आवश्यकता को उजागर किया जो पहचान और निवास के नियमों से बाधित न हो।



राज्य और स्थानीय एजेंसियों को महामारी से उबरने के लिए समुदाय पर आधारित या 'कम्युनिटी बेस्ड' मॉडलों को अपनाना चाहिए। उदाहरण के लिए, केरल राज्य ने और धारावी (एशिया का सबसे बड़ी शहरी बस्ती) ने समुदाय के प्रख्यात व्यक्तियों और सिविल सोसाइटी संघठनों की सहायता से स्क्रीनिंग और कांटेक्ट ट्रेसिंग जैसे कठिन कार्य भी पूरे किये।